



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 378]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 26, 2012/श्रावण 4, 1934

No. 378]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 26, 2012/SHRAVANA 4, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 591(अ).—केंद्रीय सरकार, गोवा, दमण और दीव (प्रशासन) अधिनियम, 1962 (1962 का 1) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन महाराष्ट्र राज्य में यथा प्रवृत्त बंबई पुलिस ऐक्ट, 1951 (1951 का बम्बई अधिनियम XXII) की धारा 1, धारा 2, धारा 55, धारा 56, धारा 57, धारा 58, धारा 59, धारा 60, धारा 61, धारा 62, धारा 63, धारा 63कक, धारा 71, धारा 72, धारा 141, धारा 142, धारा 143, धारा 155, धारा 156, धारा 157, धारा 157क, धारा 158, धारा 159, धारा 160, धारा 160 और धारा 163 को दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में विस्तारित करती है, अर्थात् :--

उपांतरण

1. साधारण- अधिनियम की पूर्वोक्त पूर्णतया धाराओं में, जब तक कि अन्यथा निदेशित न किया जाए, “राज्य सरकार”, शब्दों के स्थान पर, “प्रशासक” शब्द रखे जाएंगे और किसी भी ऐसे वाक्य में, जिसमें “राज्य सरकार”, शब्द आते हैं, उनमें ऐसे पारिणामिक संशोधन भी किए जाएंगे जो व्याकरण के नियम अपेक्षा कर सकें।

2. धारा 1 में,—

(क) उपधारा (1) में, “बम्बई पुलिस अधिनियम, 1951” शब्द और अंकों के स्थान पर, “दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में यथाविस्तारित, बम्बई पुलिस अधिनियम, 1951” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, “महाराष्ट्र राज्य” शब्दों के स्थान पर, “दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

“(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो प्रशासक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ पर किसी ऐसे उपबंध में कोई निर्देश इसको उस उपबंध के प्रारंभ के प्रतिनिर्देश के रूप में नियत किया जाएगा।

3. धारा 2 में,-

(क) खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

(1) “प्रशासक” से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है ;

(ख) खंड (2), खंड (3), खंड (4) और खंड (5) का लोप किया जाएगा ;

(ग) खंड (6) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(6) “निरीक्षक” से दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के लिए नियुक्त किया गया पुलिस का निरीक्षक अभिप्रेत है ;

(घ) खंड (7) और खंड (7क) का लोप किया जाएगा ;

(ङ) खंड (9) और खंड (10) का लोप किया जाएगा ;

(च) खंड (11) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(11) “पुलिस अधिकारी” से दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के लिए नियुक्त या नियुक्त होने के लिए समझा गया पुलिस बल का कोई सदस्य अभिप्रेत है ;”

(छ) खंड (12), खंड (13), खंड (13क), खंड (14), खंड (16) और खंड (17) का लोप किया जाएगा ।

4. धारा 55 में,-

(क) “जब कभी बृहत् मुम्बई और अन्य क्षेत्रों में जिसमें धारा 7 के अधीन आयुक्त नियुक्त किया गया है, आयुक्त को और उन जिलों में जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षण, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त हैं” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “जब कभी जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होगा” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर या ऐसे क्षेत्र और कोई जिला या जिलों या उसका कोई भाग या उससे संसक्त क्षेत्र से बाहर जाने के लिए ऐसे समय में, जो ऐसा अधिकारी विहित करेगा और यथास्थिति, क्षेत्र और संसक्त जिलों या उसके भाग में प्रवेश नहीं करने या” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे मार्ग और ऐसे समय, जो ऐसा अधिकारी विहित करेगा, द्वारा उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर और उस क्षेत्र में प्रवेश न करना, या” शब्द रखे जाएंगे ।

5. धारा 56 में,-

(क) “जब कभी आयुक्त को बृहत् मुम्बई में ऐसा प्रतीत होगा या उन क्षेत्रों में जिनके लिए धारा 7 के अधीन आयुक्त नियुक्त किया गया है और अन्य क्षेत्र या क्षेत्रों जिसके लिए राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस धारा के उपबंध जिला मजिस्ट्रेट या उस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त खंड मजिस्ट्रेट को विस्तारित कर सकेगी” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “जब कभी जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होगा” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर और कोई जिला या जिलों या उसके किसी भाग या ऐसे भागों से संसक्त भाग से और ऐसे समय के भीतर, जो उक्त अधिकारी विहित कर सके, और यथास्थिति, उस क्षेत्र या क्षेत्रों और संसक्त जिला या जिलों या उसके भाग जिससे उसे स्वयं का हटाने के लिए निदेश दिया गया था” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे मार्ग और ऐसे समय, जो ऐसा अधिकारी विहित करेगा, द्वारा उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर और उस क्षेत्र में प्रवेश न करना, या” शब्द रखे जाएंगे ।

6. धारा 57 में,-

(क) खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“(क) भारतीय दंड संहिता के अध्याय 12, अध्याय 16 या अध्याय 17 के अधीन किसी अपराध का ; या

(ख) अनेतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 4) के उन्मूलन के अधीन किसी अपराध का दोबारा ;

(ग) दमण और दीव के स्वतंत्र क्षेत्रों के आवकारी अधिनियम, 1956 या दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य तत्स्थानी विधि के अधीन किसी अपराध के तीन वर्ष की अवधि के भीतर तीन बार,"

(ख) इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट" शब्दों के स्थान पर, "जिला मजिस्ट्रेट" शब्द रखे जाएंगे ।

(ग) "उसकी अधिकारिता के भीतर स्थानीय सीमाएं या ऐसे क्षेत्र और कोई जिला या जिले या उसका कोई भाग या उससे सशक्त कोई मार्ग ऐसे समय के भीतर जो अधिकारी विहित करे और यथास्थिति, उस क्षेत्र में या सशक्त जिलों में या उसके भाग में प्रवेश नहीं करना या" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे मार्ग और ऐसे समय, जो ऐसा अधिकारी विहित करेगा, द्वारा उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर, और उस क्षेत्र में प्रवेश न करना, या" शब्द रखे जाएंगे ।

7. धारा 58 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"58. धारा 55, धारा 56 और धारा 57 के अधीन आदेश के प्रचालन की अवधि- किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने के लिए धारा 55, धारा 56 या धारा 57 के अधीन किया गया कोई निदेश ऐसे अवधि के लिए होगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जा सके और उस तारीख से जिसको व्यक्ति स्वयं उस क्षेत्र, जिला या जिलों या उपरोक्त भाग से हटता है या हटाया जाता है, दो वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगा ।"

8. धारा 59 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"59. धारा 55, धारा 56 या धारा 57 के अधीन पारित किए गए आदेश के पूर्व सुनवाई किया जाना - (1) उक्त धाराओं में से किसी के अधीन कार्य कर रहे किसी अधिकारी, व्यक्ति जो उस अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी निरीक्षक की पंक्ति से ऊपर का है, के विरुद्ध धारा 55, धारा 56 या धारा 57 के अधीन कोई आदेश पारित होता है, उसके विरुद्ध तात्किक अभिकथन की साधारण प्रकृति को लिखित में व्यक्ति को सूचित करेगा और उन्हें स्पष्टीकरण देने के संबंध में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देगा । यदि ऐसा व्यक्ति उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी साक्षियों की परीक्षा के लिए आवेदन करता है तो संबद्ध प्राधिकारी या अधिकारी ऐसे आवेदन को मंजूर करेगा ; और ऐसे साक्ष्यों की तब तक परीक्षा नहीं करेगा जब तक लिखित में कारण लेखबद्ध न कर दिए जाएं, प्राधिकारी या अधिकारी की यह राय है कि ऐसा आवेदन परेशानी या विलंब के प्रयोजन के लिए किया गया है । ऐसे व्यक्ति द्वारा रखा गया कोई लिखित कथन मामले के अभिलेख के साथ फाइल किया जाएगा । ऐसा व्यक्ति अपने स्पष्टीकरण और उसके द्वारा पेश किए गए साक्षी के प्रयोजन के लिए किसी अधिवक्ता या अटर्नी द्वारा इस धारा के अधीन कार्यवाही कर रहे अधिकारी के समक्ष उपसंजात होने के लिए हकदार होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही कर रहा कोई प्राधिकारी या अधिकारी किसी व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 55, धारा 56 या धारा 57 के अधीन किए जाने के लिए कोई आदेश प्रस्तावित है, उपस्थिति को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा करेगा और जांच के दौरान ऐसी उपस्थिति के लिए प्रतिभूति बंधपत्र के साथ या प्रतिभू के बिना पारित करेगा । यदि कोई व्यक्ति यथापेक्षित प्रतिभूति बंधपत्र पारित करने में असफल रहता है या जांच के दौरान अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने में असमर्थ रहता है तो यह किसी अधिकारी या प्राधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह जांच आगे बढ़ाए और उस पर ऐसे आदेश जो उसके विरुद्ध पारित होने के लिए प्रस्तावित थे, पारित करे ।"

9. धारा 60 की उपधारा (1) में, "धारा 55, धारा 56, धारा 57 या धारा 57क" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 55, धारा 56 या धारा 57" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

10. धारा 61 में, "धारा 55, धारा 56, धारा 57 या धारा 57क" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 55, धारा 56 या धारा 57" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

11. धारा 62 में,-

(i) उपधारा (1) में, “धारा 55, धारा 56, धारा 57 या धारा 57क” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “धारा 55, धारा 56 या धारा 57” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

(ii) उपधारा (2) में,-

“(क) “क्षेत्र में प्रवेश करने या लौटने के लिए आदेश किया गया है, जिसमें संसक्त जिले या उसके भाग भी सम्मिलित हैं” शब्दों के स्थान पर, “उस क्षेत्र में प्रवेश करने या लौटने के लिए आदेश दिया गया है, जिसे” शब्द रखे जाएंगे ; और

(ख) “या स्वयं को ऐसे क्षेत्र या वे क्षेत्र संनिकट जिलों के या उसके भाग” शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, लोप किया जाएगा ।

12. धारा 63 में,-

(क) उपधारा (1) में, “धारा 55, धारा 56, धारा 57 या धारा 57क” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “धारा 55, धारा 56 या धारा 57” शब्द और अंक रखे जाएंगे ; और

(ख) “या स्वयं को ऐसे क्षेत्र या वे क्षेत्र संनिकट जिलों के या उसके भाग” शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, लोप किया जाएगा ।

13. धारा 63कक में-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

“(1) प्रशासक या उस, निमित्त प्रशासक द्वारा विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य अधिकारी समान परिस्थितियों में और समान रीति में, धारा 55, धारा 56 या धारा 57 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों का प्रयोग करेगा ।” ; और

(ख) उपधारा (2) में, “धारा 55, धारा 56, धारा 57 या धारा 57क” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “धारा 55, धारा 56 या धारा 57” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

14. धारा 71 में,-

(क) “विनियम और” शब्दों का लोप किया जाएगा ; और

(ख) “धारा 43” शब्द और अंकों का लोप किया जाएगा ।

15. धारा 72 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

“72. जब पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करे- कोई अधिकारी मजिस्ट्रेट से किसी आदेश के बिना और वारंट के बिना ऐसे किसी व्यक्ति के गिरफ्तार कर सकेगा जिसने धारा 56, धारा 57 या धारा 63कक के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन किया है ।”

16. धारा 141 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

“141. धारा 55, धारा 56, धारा 57 या धारा 63कक के अधीन निदेशों के उल्लंघन के लिए शास्ति -जो कोई धारा 55, धारा 56, धारा 57 या धारा 63कक के अधीन जारी किसी निदेश का पालन करने का विरोध करता है, अवज्ञा करता है या चूक करता है या ऐसे किसी निदेश का दुष्प्रेरण से विरोध या अवज्ञा करता है तो सिद्धदोष ठहराने पर उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा किंतु कारण लेखबद्ध करने के सिवाए चार मास से कम नहीं होगा और जुर्माने से भी दायी होगा ।”

17. धारा 142 में,-

(क) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(क) धारा 55, धारा 56, धारा 57 या धारा 63कक के अधीन उसको जारी किसी निदेश के उल्लंघन में वह उस क्षेत्र में जिसके लिए उसे स्वयं को हटाए जाने का निदेश दिया गया है, प्रवेश करता है या लौटता है ;” ;

(ख) खंड (ख) में, “उपरोक्त जिला या उसके किसी भाग” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

18. धारा 157 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

“157. धारा 55, धारा 56, धारा 57 या धारा 63कक के अधीन जारी निदेशों के उल्लंघन के लिए अभियोजनों में पूर्वधारणा- तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आदेश के किसी प्रमाणित प्रति के प्रस्तुत किए जाने पर धारा 55, धारा 56, धारा 57 या धारा 63कक के अधीन जारी निदेशों के उल्लंघन के लिए किसी अपराध के अभियोजन में तत्प्रतिकूल साबित नहीं होने तक और साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा तो यह उपधारणा की जाएगी कि -

(क) इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके लिए आदेश पारित किया गया था ;

(ख) आदेश करने वाले प्राधिकारी का यह समाधान हो गया था कि उन आधारों पर उन प्रयोजनों के लिए, जिनके लिए उन्हें किया गया, विद्यमान थे, उसको किया जाना आवश्यक था ; और

(ग) आदेश अन्यथा विधिमान्य था और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप था ।

19. धारा 157क में “कोई आयुक्त” शब्दों और “आयुक्त” शब्द, जहां-जहां वे आते हैं, के स्थान पर “प्रशासक” शब्द रखा जाएगा ।

20. धारा 159 में, “कोई राजस्व आयुक्त, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के किसी उपबंध या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी नियम, किए गए आदेश या दिए गए निदेश द्वारा उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य या उसे प्रदत्त किसी प्राधिकार के अनुसरण या आशयित अनुसरण में सदभावपूर्णक किए गए कृत्य के कारण किसी शास्ति या नुकसानी के संदाय का दायी नहीं होगा” शब्दों के स्थान पर, “प्रशासक, कोई मजिस्ट्रेट या कोई पुलिस अधिकारी, इस अधिनियम के किसी उपबंध या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी नियम, किए गए आदेश या दिए गए निदेश द्वारा उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य या उसे प्रदत्त किसी प्राधिकार के अनुसरण या आशयित अनुसरण में सदभावपूर्णक किए गए कृत्य के कारण किसी शास्ति या नुकसानी के संदाय का दायी नहीं होगा” शब्द रखे जाएंगे ।

21. धारा 161 की उपधारा (1) में “राजस्व आयुक्त, आयुक्त” शब्द और “राजस्व आयुक्त, आयुक्त” शब्दों के स्थान पर “प्रशासक” शब्द रखा जाएगा ।

[फा. सं. यू-11015/1/2011-यूटीएल]

के. के. पाठक, संयुक्त सचिव

उपाबंध

दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र को यथाविस्तारित बम्बई पुलिस अधिनियम, 1951

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बम्बई पुलिस अधिनियम, 1951 है ।

(2) यह संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य पर विस्तारित है ।

(3) यह ऐसी तारीख को, जो राज्य सरकार इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सके और राज्य के उस भाग में जिसमें बाम्बे पुलिस (एक्सटेंशन एंड अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1959 (1959 का बाम्बे XXXIV) विस्तारित है, प्रवृत्त होगा, यह ऐसी तारीख को, जो सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सके, प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं - इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात संदर्भ या विषय के प्रतिकूल न हो-

“पशु” में हाथी, ऊँट, घोड़े, गधे, खच्चर, भेड़, बकरियाँ, सुअर सम्मिलित हैं ;

(2) से (5) का लोप किया गया है ।

(5-क) “भोजनालय” से कोई ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जिसमें जनता को प्रवेश दिया जाता है और जहां किसी भी प्रकार का खाद्य या पेय ऐसे स्थान के स्वामित्व वाले या किसी हित वाले या प्रबंध करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा परिसर में खपत के लिए प्रदाय किया जाता है और जिसमें जलपान गृह, बोर्डिंग हाउस, काफी हाउस या ऐसी कोई दुकान सम्मिलित है, जहां किसी भी प्रकार का खाद्य या पेय खपत के लिए जनता को प्रदाय किया जाता है किन्तु इसमें “लोक मनोरंजन का स्थान” सम्मिलित नहीं है ।

(6) “महानिरीक्षक” “विशेष महानिरीक्षक”, “अपर महानिरीक्षक”, “आयुक्त”, “उप महानिरीक्षक”, “उपायुक्त”, “सहायक आयुक्त”, “जिला अधीक्षक”, “अपर अधीक्षक”, “सहायक अधीक्षक” और “उप अधीक्षक” से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या नियुक्त होने के लिए समझे जाने वाले संबंधित पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस विशेष महानिरीक्षक, पुलिस अपर महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक (जिसमें धारा 8-क के अधीन नियुक्त किया गया बेतार पुलिस निदेशक और पुलिस उप महानिरीक्षक सम्मिलित हैं) पुलिस उपायुक्त, पुलिस सहायक आयुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक (जिसमें धारा 8-क या धारा 22-क के अधीन नियुक्त किया गया अधीक्षक सम्मिलित है), पुलिस अपर अधीक्षक, पुलिस सहायक अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक अभिप्रेत हैं।

(7) का लोप किया गया।

(7क) का लोप किया गया।

(8) “स्थान” में कोई भवन, कोई तम्बू, कोई बूथ या अन्य उत्थापन, चाहे स्थायी हों या अस्थायी या कोई ऐसा क्षेत्र जो परिबद्ध है या खुला है, सम्मिलित है।

(9) से (10) का लोप किया गया।

(11) “पुलिस अधिकारी” से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया या नियुक्त होने के लिए समझा गया पुलिस बल का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसमें धारा 21 या धारा 22 के अधीन नियुक्त किया गया कोई विशेष या कोई अपर पुलिस अधिकारी सम्मिलित है।

(12) से (17) का लोप किया गया।

3. से 54 का लोप किया गया।

55. गैंगों और व्यक्तियों के निकाय का परिक्षेपण-

जहां वृहत् बम्बई और उन क्षेत्रों में जिसमें धारा 7 के अधीन आयुक्त नियुक्त किया गया है, आयुक्त को और जिला में जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त है, यह प्रतीत होता है कि उसके प्रभार के क्षेत्र में किसी गैंग या व्यक्तियों के निकाय का संचलन या पड़ाव से यह खतरा या खतरे का संकेत या युक्तियुक्त आशंका कारित है या कारित होने का अनुमान है कि ऐसे गैंग या निकाय या उसके सदस्यों द्वारा विधिविरुद्ध योजना बनाई जाती है तो ऐसा अधिकारी, ऐसे गैंग या निकाय के प्रमुख या मुख्य आदमी होने के लिए प्रतीत होने वाले व्यक्तियों को संबोधित अधिसूचना को मुनादी या अन्यथा द्वारा प्रकाशित करके ऐसा अधिकारी जो वह ठीक समझे, ऐसे गैंग या ऐसे निकाय के सदस्यों को उनके द्वारा संचालित जो और खतरा या उनमें से प्रत्येक के परिक्षेपण के लिए उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्र या ऐसा क्षेत्र और कौं जिला या जिलों उसके कोई भाग या उसमें संसक्त क्षेत्र से बाहर जाने के लिए ऐसे समय में जो ऐसा अधिकारी विहित करेगा और यथास्थिति, क्षेत्र और संसक्त जिलों या उसके भाग में प्रवेश नहीं करने या उस स्थान से, जिसमें प्रत्येक को स्वयं के लिए हटाने के लिए निदेश दिया गया था नहीं लौटने के लिए निदेश दे सकेगा।

56. उन व्यक्तियों को हटाया जाना जो अपराध करने वाले हैं

जब कभी आयुक्त को वृहत् बम्बई में ऐसा प्रतीत होगा या उन क्षेत्रों में जिनके लिए धारा 7 के अधीन आयुक्त नियुक्त किया गया है और अन्य क्षेत्र या क्षेत्रों जिसके लिए राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस धारा के उपबंध जिला मजिस्ट्रेट या उस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त खंड मजिस्ट्रेट को विस्तारित कर सकेगी कि-

(क) किसी व्यक्ति के संचलन या कार्य से व्यक्ति या संपत्ति को भय, खतरा या हानि कारित कर रहे हैं या कारित करने के लिए प्रकल्पित हैं; या

(ख) विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार है, कि ऐसा व्यक्ति, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 12, अध्याय 16 या अध्याय 17 के अधीन दंडनीय किसी अपराध में बल या हिंसा अंतर्वलित करते हुए किसी अपराध को करने में लिप्त है या लिप्त होने वाला है, या ऐसे किसी अपराध के दुष्परण में लिप्त है या होने वाला है और जब ऐसे अधिकारी की यह राय है कि साक्षी, अपने व्यक्तियों या संपत्ति की सुरक्षा के बारे में उन्हे भय के कारण से ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जनता में साक्ष्य देने के लिए आगे आने के लिए इच्छुक नहीं है।

(खख) यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि ऐसा व्यक्ति- (1) ऐसी रीति में जो महाराष्ट्र प्रिवेंशन आफ कम्यूनल, एंटी सोशल एंड अदर डेंजरस एक्टिविटीज ऐक्ट, 1980 में यथा परिभाषित लोक व्यवस्था बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है या (2) ऐसी रीति में जो चोर बाजारी निवारण और आवश्यक

वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का 7) की धारा 3 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित समुदाय की आवश्यक वस्तु के प्रदायों के बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, कार्य कर रहा है या कार्य करने वाला है।

(ग) किसी अप्रवासी के लगातार निवास के परिणामस्वरूप महामारी बीमारी के प्रकोपन की संभावना है तो उक्त अधिकारी उस पर तामील सम्यक् रूप से लिखित आदेश द्वारा या मुनादी द्वारा या अन्यथा, जो वह ठीक समझे, ऐसे व्यक्ति या ऐसे अप्रवासी के स्वयं के संचालन, जो हिंसा और भय या ऐसा प्रतिकूल कार्य रोकने के लिए आवश्यक प्रतीत हों या ऐसी बीमारी के प्रकोपन या फैलाव को रोकने या उसकी अधिकारिता या ऐसे क्षेत्र और कोई जिला या जिले या उसके किसी भाग, ऐसे मार्ग से उससे संसक्त है की स्थानीय सीमाओं के भीतर और ऐसे समय के भीतर जो उक्त अधिकारी विहित कर सके, क्षेत्र के बाहर हटने और यथास्थिति, उक्त क्षेत्र या क्षेत्रों और ऐसे संसक्त जिलों या उसके किसी भाग जिसमें उसे स्वयं को हटाने का निदेश दिया गया था, प्रवेश नहीं करने या नहीं लौटने का निदेश देगा।

57. कतिपय अपराधों के सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्तियों का हटाया जाना-

(क) यदि कोई व्यक्ति-

(i) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 12, अध्याय 16 या अध्याय 17 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

(ii) बाम्बे प्राहिबिशन ऐक्ट, 1949 (1949 का बम्बई XLV) की धारा 65, धारा 66क या धारा 68 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है ;

(iii) सप्रेशन आफ इममोरल ट्रेफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स ऐक्ट, 1956 (1956 का सीआई वी) की धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6 या धारा 9 के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

(iv) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 135 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

(v) धारा 4 के अधीन किसी अपराध या बाम्बे प्रिवेशन आफ गैम्बलिंग ऐक्ट, 1867 (1867 का बाम्बे IV) की धारा 12 के खंड (क) या धारा 12क के अधीन किसी सार्वजनिक गली या आम रास्ता या किसी ऐसे स्थान में जिसमें जनता की पहुँच है या पहुँच रखने के लिए अनुज्ञात किया गया है या किसी घुड़दौड़ मैदान में बाजी स्वीकार करने के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

(ख) बाम्बे प्राहिबिशन ऐक्ट, 1949 (1949 का बान XXV) के अधीन कोई अपराध जो धारा 66, धारा 66क या धारा 68 के अधीन अपराध नहीं है, के लिए दो बार या इससे अधिक सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

(ग) इस अधिनियम की धारा 122 या धारा 124 के अधीन किसी अपराध के लिए दो बार या इससे अधिक के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट, यदि उसका यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति की उसी प्रकार के किसी अपराध, जिसके लिए वह सिद्धदोष ठहराया गया था, में स्वयं के पुनः लिप्त रहने की संभावना है ऐसे व्यक्ति की ऐसे क्षेत्र में उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर और किसी जिला या जिलों, उसके किसी भाग, ऐसे मार्गों से संसक्त भाग से और ऐसे समय के भीतर जो उक्त अधिकारी विहित कर सके और यथास्थिति, उस क्षेत्र या क्षेत्रों और ऐसे संसक्त जिला या जिलों या उसके किसी भाग, जिससे उसे स्वयं का हटाने के लिए निदेश दिया गया था, प्रवेश नहीं करने या नहीं लौटने का निदेश दे सकेगा।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजन के लिए, “उसी तरह के किसी अपराध जिसके लिए वह सिद्धदोष ठहराया गया था” से अर्थ होगा-

(i) भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) के किन्हीं अध्यायों के अधीन आने वाला कोई अपराध जिसके लिए खंड (क)(i) में उल्लिखित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्ति की दशा में, उस तारीख से जिसको व्यक्ति स्वयं को हटाता है या उक्त क्षेत्र जिला या जिलों या उसके भाग से हटाया जाता है ;

(ii) उपखंड (i), उसके (ख) और (ग) को अपवर्जित करते हुए उक्त खंडों में संबंधित उल्लिखित अधिनियमों के उपबंधों के अधीन आने वाले किसी अपराध, खंड (क) में उल्लिखित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति की दशा में।

57-क का लोप किया गया ।

धारा 55, धारा 56, धारा 57 और धारा 57क के अधीन आदेशों के प्रचालन की अवधि- यथास्थिति, किसी विशिष्ट क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र और किसी जिले या जिलों या उसके किसी भाग या उससे संसक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने के लिए धारा 55, धारा 56 या धारा 57 के अधीन किया गया कोई निदेश ऐसी अवधि के लिए होगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जा सके और किसी भी दशा में उस तारीख से जिसको व्यक्ति उपरोक्त क्षेत्र, जिला या जिलों या भाग से स्वयं को हटाता है या हटाया जाता है दो वर्ष से अनधिक के लिए होगा ।

59. धारा 55, धारा 56, धारा 57 और धारा 57क के अधीन पारित किए गए आदेश के पूर्व सुनवाई करना-

(1) किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध धारा 55, धारा 56, धारा 57 या धारा 57क के अधीन पारित किए गए आदेश के पूर्व, उक्त धाराओं में किसी धारा के अधीन कार्य कर रहा है कोई अधिकारी या उस अधिकारी द्वारा प्राधिकृत निरीक्षक की पंक्ति से ऊपर की पंक्ति का कोई अधिकारी उसके विरुद्ध तात्त्विक अभिकथनों की साधारण प्रकृति को लिखित में व्यक्ति को सूचना देगा और उनके संबंध में स्पष्टीकरण देने का उसे युक्तियुक्त अवसर देगा । यदि ऐसा व्यक्ति उसके द्वारा प्रस्तुत किसी साक्षी की परीक्षा लिए ऐसा आवेदन करता है, संबद्ध प्राधिकारी या अधिकारी ऐसा आवेदन मंजूर करेगा ; और ऐसे साक्षी की परीक्षा करेगा जब तक कि कारण लिखित में अभिलिखित न हो, कि प्राधिकारी या अधिकारी की यह राय है कि ऐसा आवेदन तंग करने या विलंब के प्रयोजन के लिए किया गया है । ऐसे व्यक्ति द्वारा रखा गया लिखित कथन मामले के अभिलेख के साथ फाइल किया जाएगा । ऐसा व्यक्ति अपने स्पष्टीकरण देने और उसके द्वारा पेश किए गए साक्षियों की परीक्षा के प्रयोजन के लिए किसी अधिवक्ता या अटर्नी द्वारा इस धारा के अधीन कार्यवाही कर रहे अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का हकदार होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही कर रहा कोई प्राधिकारी या अधिकारी किसी व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 55, धारा 56, धारा 57 और धारा 57क के अधीन कोई आदेश किया जाना प्रस्तावित है, की उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए उसके समक्ष ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा और जांच के दौरान ऐसी उपस्थिति के लिए प्रतिभू के साथ या उनके बिना प्रतिभूति बंधपत्र पारित करने की अपेक्षा करेगा यदि व्यक्ति जांच के दौरान ऐसा अपेक्षित प्रतिभूति बंधपत्र पारित करने में असफल रहता है या अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है तो यह अधिकारी या प्राधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा कि जांच अग्रसर करे और तदुपरि ऐसे आदेश जो उसके विरुद्ध पारित होने के लिए प्रस्तावित थे, पारित किया जा सकेगा ।

60. अपील- (1) धारा 55, धारा 56, धारा 57 और धारा 57क के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा ।

(2) इस धारा के अधीन कोई अपील ज्ञापन के रूप में उसके विरुद्ध अपील किए गए आदेश के आक्षेपों के बताए गए सुसंगत आधार पर दो प्रतियों में की जाएगी और उसके साथ वह आदेश या उसकी प्रमाणित प्रति संलग्न होगी ।

(3) ऐसी अपील के प्राप्त होने पर, राज्य सरकार व्यक्तिगत रूप से या प्लीडर, अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देगी और ऐसी अन्य जांच के पश्चात्, यदि कोई है, जो आवश्यक समझे, तदनुसार इसके आदेश के विरुद्ध की गई अपील को पुष्ट, फेरफार या रद्द या अपास्त कर सकेगी और तदनुसार आदेश कर सकेगी ;

परंतु उसके विरुद्ध अपील किए गए आदेश, अपील के निपटान के लिए तब तक लंबित रहेगा जब तक राज्य सरकार अन्यथा निदेश न दे ।

(4) इस धारा के लिए अपील के लिए उपबंधित तीस दिन की अवधि की गणना में, उसके विरुद्ध अपील किए गए आदेश की प्रमाणित प्रति मंजूर किए जाने के लिए गए समय को अपवर्जित किया जाएगा ।

61. कतिपय मामलों में राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश की अंतिमता

राज्य सरकार द्वारा धारा 55, धारा 56, धारा 57 और धारा 57क के अधीन या धारा 60 के अधीन राज्य सरकार द्वारा पास्ति कोई आदेश किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा सिवाए उन आधार के जिसमें आदेश करने वाला प्राधिकारी या इसके द्वारा किसी प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 59 की उपधारा (1) में अधिकथित प्रक्रिया का पालन न किया हो कि संबद्ध प्राधिकारी के समक्ष कोई सामग्री नहीं थी जिससे उस आधार पर आदेश आधारित किया जा सकता कि उक्त प्राधिकारी कि यह राय नहीं थी कि साक्षी उनकी बाबत व्यक्तियों के विरुद्ध जनता में साक्ष्य देने के लिए आगे आने के लिए अनिच्छुक थे जिसके विरुद्ध धारा 56 के अधीन आदेश किया गया था ।

62. क्षेत्र को छोड़ने और हटाए जाने के पश्चात् उसमें प्रवेश के लिए व्यक्ति के असफल होने पर प्रक्रिया -

(1) यदि कोई व्यक्ति, जिसको क्षेत्र से स्वयं को हटाए जाने के लिए धारा 55, धारा 56, धारा 57 और धारा 57क के अधीन निदेश जारी किए गए हैं-

(i) यथानिर्देशित स्वयं को हटाए जाने में असफल रहता है ; या

(ii) इस प्रकार स्वयं को हटाए जाने पर उपधारा (2) में यथा उपबंधित आदेश करने वाले प्राधिकारी की लिखित में अनुज्ञा के सिवाए आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर क्षेत्र में प्रवेश करता है तो संबद्ध प्राधिकारी उस क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान की पुलिस अभिरक्षा में उसे गिरफ्तार कराएगा और हटाएगा जो उक्त प्राधिकारी प्रत्येक मामले में विहित करे ।

(2) धारा 55, धारा 56, धारा 57 और धारा 57क के अधीन किसी आदेश को करने वाला कोई प्राधिकारी लिखित में ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसकी बाबत क्षेत्र में प्रवेश करने या लौटने के लिए आदेश किया गया है जिसमें संसक्त जिले या उसके भाग भी सम्मिलित हैं, जिसे उसे स्वयं को हटाए जाने के निदेश किया गया था, प्रवेश करने की अनुज्ञा कर सकेगा और उन शर्तों के अधीन, जो ऐसे अनुज्ञा में विनिर्दिष्ट की जा सकें और उसे अधिरोपित शर्तों के सम्यक् अनुपालन के लिए प्रतिभू सहित या उसके बिना बंधपत्र करने की अपेक्षा होगी । पूर्वोक्त प्राधिकारी किसी भी समय कोई ऐसी अनुज्ञा का प्रतिसंहरण कर सकेगा । कोई व्यक्ति, जो ऐसी अनुज्ञा के साथ ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है या लौटता है, वह अधिरोपित शर्तों का पालन करेगा और उस अस्थायी अवधि, जिसके लिए उसे प्रवेश करने या लौटने के लिए अनुज्ञात किया गया था, की समाप्ति पर या ऐसी अनुज्ञा के पूर्व प्रतिसंहरण पर स्वयं को ऐसे क्षेत्र या, वे क्षेत्र और संनिकट जिलों के या उसके भाग से स्वयं को हटाएगा और उसमें नई अनुज्ञा के बिना धारा 55, धारा 56, धारा 57 और धारा 57क के अधीन किए गए मूल आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि की शेष अवधि के भीतर उसमें प्रवेश नहीं करेगा या उसमें नहीं लौटेगा यदि ऐसा व्यक्ति अधिरोपित किन्हीं शर्तों का पालन करने में असफल रहता है या तदनुसार स्वयं को हटाए जाने के पश्चात् ऐसे क्षेत्र या क्षेत्र और किन्हीं संसक्त जिलों या उनके भाग में बिना नई अनुज्ञा के प्रवेश करता है या लौटता है तो संबद्ध प्राधिकारी उसे गिरफ्तार कराएगा और क्षेत्र से बाहर ऐसे स्थान में पुलिस अभिरक्षा में हटाएगा जो प्राधिकारी प्रत्येक मामले में विहित करे ।

63. उस क्षेत्र से जिसमें व्यक्ति को स्वयं हटाए जाने का निदेश किया गया था, में प्रवेश करने या वापस लौटने की अस्थायी अनुज्ञा - (1) राज्य सरकार या उस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त कोई अधिकारी आदेश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसकी बाबत धारा 55, धारा 56, धारा 57 और धारा 57क के अधीन आदेश किया गया था, यथास्थिति, उस क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र और संसक्त जिलों या उसके किसी भाग में ऐसी शर्तों के अधीन, जो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रवेश करने या लौटने की अनुज्ञा दे सकेगा जिससे उसे स्वयं हटाए जाने के लिए निदेश किया गया था और जिसे ऐसा व्यक्ति स्वीकार करता है और किसी समय ऐसी अनुज्ञा का प्रतिसंहरण किया जा सकेगा ।

(2) यथास्थिति, क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र और किसी संसक्त जिलों या उसके किसी भाग में जिससे उसे स्वयं हटाए जाने के लिए निदेश किया गया था जिससे प्रवेश करने या लौटने के लिए उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को अनुज्ञा देते समय राज्य सरकार या ऐसा अधिकारी अधिरोपित शर्तों के अनुपालन के लिए प्रतिभू सहित या उसके बिना बंधपत्र करने की अपेक्षा करेगा ।

(3) यथास्थिति, क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र और किसी संसक्त जिलों या उसके किसी भाग में प्रवेश करने या लौटने के लिए उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात कोई व्यक्ति ऐसे समय और स्थान में स्वयं को आदेश में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को अभ्यर्पित करेगा ।

63कक. राज्य सरकार और विशेष रूप से सशक्त अधिकारियों की बाहर करने की शक्तियां- (1) राज्य सरकार या उस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त कोई अधिकारी समान परिस्थितियों और समान रीति में धारा 55, धारा 56, धारा 57 और धारा 57क के अधीन प्रयोक्ताव्य शक्तियों का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए, जिसके लिए वह आयुक्त द्वारा आयुक्त की नियुक्ति की जाती है और किसी जिले में राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त उस रूप से सशक्त जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट अधीक्षक इस उपातरण के साथ करेगा कि राज्य सरकार या विशेष रूप से सशक्त अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह, यथास्थिति, ऐसे गैंग या निकाय के सदस्यों या व्यक्तियों या अप्रवासियों अथवा सिद्धदोष व्यक्तियों या भिखारियों के रूप में घोषित व्यक्ति को किसी स्थानीय क्षेत्र या किसी ऐसे क्षेत्र और किसी जिले या उसके भाग, चाहे संसक्त हो या नहीं, से स्वयं को हटाने और प्रवेश न करने अथवा वापस न आने का निदेश दे ।

(2) धारा 58, धारा 59, धारा 60, धारा 61, धारा 62 और धारा 63 के उपबंध इस धारा के अधीन किन्हीं शक्तियों के प्रयोग में आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे जो धारा 55, धारा 56, धारा 57 और धारा 57क के अधीन किन्हीं शक्तियों के प्रयोग में लागू होते हैं ।

64 से 70 तक का लोप किया गया ।

71. धारा 43, धारा 55, धारा 56, धारा 57, धारा 57क या धारा 63कक के अधीन जारी किए गए आदेशों के कार्यान्वयन को देखने का पुलिस के कर्तव्य ।

पुलिस का यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि धारा 43, धारा 55, धारा 56, धारा 57, धारा 57क या धारा 63कक के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा बनाए गए प्रत्येक विनियम और निदेश का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है, व्यक्तियों को चेतावनी दे, जो अनभिज्ञता के कारण उनका पालन करने में असफल रहते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करे, जो उसका जानबूझकर अवज्ञा करता है ।

72. जब पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा ।

कोई पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट से किसी आदेश के बिना और वारंट के बिना निम्नलिखित को गिरफ्तार कर सकेगा-

(1) कोई व्यक्ति, जो धारा 121 के अधीन दंडनीय किसी अपराध से संबद्ध है या जिसके विरुद्ध व्यक्तिगत परिवार किया गया है या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त की गई है या ऐसे अपराध में संबद्ध रहने की उसकी व्यक्तिगत आशंका विद्यमान है ।

(2) कोई व्यक्ति, जो धारा 33 की उपधारा (1) के खंड (x) के अधीन नियम या किसी आदेश या धारा 36, धारा 37, धारा 56, धारा 57, धारा 57क या धारा 63कक के अधीन आदेश या अधिसूचना का उल्लंघन करता है ।

(2-क). कोई व्यक्ति, जो धारा 63-क की उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है ।

(3) कोई व्यक्ति, जो धारा 122 या धारा 136 के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करता है ।

73 से 140 का लोप किया गया ।

141. धारा 55, धारा 56, धारा 57, धारा 57क या धारा 63कक के अधीन निदेशों के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

जो कोई, धारा 55, धारा 56, धारा 57, धारा 57क या धारा 63कक के अधीन जारी किसी निदेश के पालन का विरोध करता है या अवज्ञा करता है या पालन करने में असफल रहता है या ऐसे किसी निदेश के दुष्प्रेरित रूप से विरोध करता है या अवज्ञा करता है, सिद्धदोष होने पर वह कारावास से दंडित किया जाएगा, जो एक वर्ष तक हो, किन्तु लिखित में कारण अभिलिखित करने के सिवाए चार मास से कम नहीं होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

142. किसी व्यक्ति को उस क्षेत्र में अनुज्ञा के बिना प्रवेश करने, जिससे उसे हटाने का निदेश दिया गया है या अस्थायी रूप से लौटने की अनुज्ञा होने पर अधिक समय तक रुकने के लिए शास्ति

परिस्थितियों में व्यक्ति को गिरफ्तार करने और हटाने में शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और धारा 62 में उपबंधित रीति में कोई व्यक्ति जो-

(क) धारा 55, धारा 56, धारा 57, धारा 57क या धारा 63कक के अधीन उसे जारी निदेश का उल्लंघन करके क्षेत्र या किसी जिला या जिलों या उसके भाग में, जिससे उसको स्वयं को हटाए जाने का निदेश दिया गया था, में अनुज्ञा के बिना प्रवेश करता है या लौटता है ;

(ख) धारा 62 की उपधारा (2) के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञा के साथ किसी ऐसे क्षेत्र या उपरोक्त जिला या उसके किसी भाग में प्रवेश करता है या लौटता है किन्तु उसके उपबंधों के तत्प्रतिकूल अस्थायी अवधि जिसके लिए उसे प्रवेश करने या लौटने के लिए अनुज्ञात किया गया था, की समाप्ति पर ऐसे क्षेत्र से बाहर स्वयं को हटाए जाने में असफल रहता है या ऐसी अनुज्ञा के पूर्वतम प्रतिसंहरण पर या ऐसी अस्थायी अवधि की समाप्ति पर स्वयं को हटाए जाने के पश्चात् या अनुज्ञा के प्रतिसंहरण पर तत्पश्चात् नई अनुज्ञा के बिना प्रवेश करता है या लौटता है, वह दोषसिद्ध होने पर ऐसी कारावास की अवधि से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित होगा किन्तु लिखित में कारण लेखबद्ध करने के सिवाए छह मास से कम नहीं होगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।

143. धारा 63 की उपधारा (3) के अनुसार अभ्यर्षण में असफल रहने के लिए शास्ति-

जो कोई, धारा 63 की उपधारा (3) के अनुसार बिना पर्याप्त कारण के अभ्यर्षण करने में असफल रहता है तो दोषसिद्धि होने पर वह कारावास से दंडनीय होगा जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

144 से 154 का लोप किया गया।

155. आदेशों और अधिसूचनाओं को साबित करने की पद्धति-

इस अधिनियम के उपबंध के अधीन राज्य सरकार द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा प्रकाशित या जारी कोई आदेश या अधिसूचना और उसके सम्यक् प्रकाशन या जारी होना राजपत्र में उसकी प्रति को पेश करके या ऐसे मजिस्ट्रेट या अधिकारी द्वारा प्रति पर हस्ताक्षर करके और इसको उपयोज्य अधिनियम की धारा के उपबंधों के अनुसार मूल रूप से प्रकाशित या जारी की गई सही प्रति को उसके द्वारा प्रमाणित करके साबित किया जा सकेगा।

156. प्ररूप में कोई त्रुटि या प्रक्रिया में अनियमितता से नियमों और आदेशों का अविधिमान्य नहीं होना-

किया गया या प्रकाशित कोई नियम, आदेश, निदेश, न्यायनिर्णयन, जांच या अधिसूचना और इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन किया गया कोई कार्य या इस अधिनियम के अधीन बनाया गया कोई नियम जो सारवान रूप से उसके अनुरूप है प्ररूप में कोई त्रुटि या प्रक्रिया में किसी अनियमितता के कारण अवैध, शून्य, अविधिमान्य या अपर्याप्त नहीं समझा जाएगा।

157. धारा 55, धारा 56, धारा 57, धारा 57क या धारा 63कक के अधीन जारी निदेशों के उत्त्संघन के लिए अभियोजनों में उपधारणा-

तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 45, धारा 56, धारा 57 या धारा 63कक के अधीन निदेश के उत्त्संघन के किसी अपराध के अभियोजन में तत्प्रतिकूल साबित नहीं हो जाने तक और आदेश की अधिप्रमाणित प्रति के पेश करने पर जिसे साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा, यह उपधारणा की जाएगी कि-

(क) इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके करने के लिए आदेश किया गया है;

(ख) आदेश करने वाले प्राधिकारी का यह समाधान था कि वे आधार या प्रयोग के लिए उसे किया जाना विद्यमान था और उसको किया जाना आवश्यक था; और

(ग) आदेश अन्यथा विधिमान्य और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप था।

157- (क) शक्तियां प्रयोग करने के लिए भारसाधक या रिक्तियों के उत्तरवर्ती अधिकारियों का सक्षम होना-

जब कभी आयुक्त, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के पद के रिक्त होने के परिणाम में कोई अधिकारी ऐसे आयुक्त, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी का पदभार ग्रहण करता है या उसके पद के लिए या तो अस्थायी या स्थायी रूप से उत्तरवर्ती होता है तो ऐसा अधिकारी, यथास्थिति, ऐसे आयुक्त, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी पर इस अधिनियम द्वारा क्रमशः प्रदान की गई और अधिरोपित संबंधित सभी शक्तियों और सभी कर्तव्यों का पालन करने के लिए सक्षम होगा।

158. वह क्षेत्र जिससे उसे स्वयं को हटाए जाने का निदेश किया गया था, में प्रवेश न करने या लौटने के लिए अनुज्ञात व्यक्ति द्वारा बंधपत्र का समपहरण-

यदि धारा 63 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात कोई व्यक्ति उक्त उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी शर्त का या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन उसके द्वारा किए गए बंधपत्र में किसी शर्त का पालन करने में असफल रहता है तो उसके बंधपत्र का समपहरण किया जाएगा और उसके द्वारा आबद्ध कोई व्यक्ति उसकी शास्ति के लिए दायी होगा या न्यायालय के समाधान में कारण बताएगा कि क्यों ऐसी शास्ति संदत्त नहीं की जानी चाहिए।

159. किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के कर्तव्य के अनुसरण में सदाभावपूर्वक किए गए कार्य के लिए शास्ति या नुकसानी के लिए दायी न होना -

कोई राजस्व आयुक्त, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के किसी उपबंध या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी नियम, किए गए आदेश या दिए गए निदेश द्वारा उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य या उसे प्रदत्त किसी प्राधिकार के अनुसरण या आशयित अनुसरण में सदाभावपूर्वक किए गए कृत्य के कारण किसी शास्ति या नुकसानी के संदाय का दायी नहीं होगा।

160. किसी लोकसेवक का दृश्यमान प्राधिकार से जारी किसी नियम, आदेश, निदेश के लिए सदभाव प्रभाव देने के लिए यथा उपरोक्त दायी न होना-

सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया या प्राधिकृत कोई लोक सेवक या व्यक्ति, राज्य सरकार या इस अधिनियम या उसके अधीन दिए गए या बनाए गए किसी नियम, आदेश या निदेश के अधीन उस निमित्त सशक्त किसी व्यक्ति द्वारा दृश्यमान प्राधिकार से जारी किसी ऐसे आदेश या निदेश का सदभाव प्रभाव देने में किसी शास्ति या नुकसानी में संदाय का दायी नहीं होगा।

161. उपरोक्तानुसार आभासी कर्तव्यों के अधीन किए गए कार्यों की बाबत वादों या अभियोजनों का ग्रहण नहीं करना या खारिज कर देना यदि यह विहित अवधि के भीतर संस्थित नहीं किया जाता है।

(1) राजस्व आयुक्त, किसी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा अभिकथित अपराध के किसी मामले में या ऐसे राजस्व आयुक्त, मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उपरोक्तानुसार आभासी या किसी ऐसे कर्तव्य या प्रभार की अधिकता में किसी कार्य द्वारा गलत अभिकथन किया गया है या जिसमें न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अपराध या गलती यदि कारित है या की गई है, पूर्वोक्त लक्षण की है तो अभियोजन वाद ग्रहण नहीं किया जाएगा और खारिज किया जाएगा यदि परिवाद किए गए कृत्य की तारीख से छह मास के पश्चात् संस्थित किया जाता है :

परंतु पुलिस अधिकारी के विरुद्ध ऐसा अभियोजन न्यायालय द्वारा ग्रहण किया जा सकेगा, यदि यह अपराध की तारीख से दो वर्ष के भीतर राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से संस्थित किया गया हो।

(2) उपरोक्तानुसार वादों में, उसकी गलत शिकायत के पर्याप्त वर्णन के साथ वाद की एक मास की सूचना दी जानी चाहिए। उपरोक्तानुसार ऐसी गलती के कारण आशयित वाद के इस मामले में वाद लाने के लिए आशयित व्यक्ति, उसकी गलत शिकायत के पर्याप्त वर्णन के साथ आशयित वाद की कम से कम एक मास की सूचना अभिकथित गलती करने वाले को देने के लिए आबद्ध होगा जिसके न हो सकने पर ऐसा वाद खारिज कर दिया जाएगा।

(3) नोटिस की तामील और संशोधन करने के लिए वादपत्र। वादपत्र में बताया जाएगा कि उपरोक्तानुसार आधारित नोटिस की तामील प्रतिवादी को कर दी गई है और ऐसी तामील की तारीख में यह कथन होगा कि यदि कोई हो, कि प्रतिवादी द्वारा क्या संशोधन किए गए हैं। उक्त नोटिस की प्रति, पृष्ठांकित वादपत्र के साथ संलग्न होगी या उसकी तामील के समय और रीति में वादी द्वारा की गई घोषणा के साथ होगी।

162. का लोप किया गया।

163. लोक सूचनाएं कैसे दी जाएं।

इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित कोई लोक सूचना लिखित में सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से होगी और उसके द्वारा प्रभावी अवस्थिति में दृश्यमान सार्वजनिक स्थानों में उसकी प्रतियां चिपका के या मुनादी द्वारा घोषणा करके या ऐसे स्थानीय समाचार पत्रों- अंग्रेजी या प्रादेशिक भाषा या हिन्दी, जो उक्त प्राधिकारी ठीक समझे, में विज्ञापन करके या ऐसे किन्हीं दो अधिक और किसी अन्य साधन जो वह ठीक समझे, उपयोग करेगा, प्रकाशित करेगा।

164 से 167 का लोप किया गया।

अनुसूची 1 का लोप किया गया।

अनुसूची 2 का लोप किया गया।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th July, 2012

G.S.R. 591(E).—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Goa, Daman & Diu (Administration) Act, 1962 (1 of 1962), the Central Government hereby extends to the Union territory of Daman & Diu sections 1, 2, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63AA, 71, 72, 141, 142, 143, 155, 156, 157, 157A, 158, 159, 160, 161, and 163 of the Bombay Police Act, 1951 (Bombay Act XXII of 1951), as in force in the State of Maharashtra, subject to the following modifications namely :-

Modifications

1. **General.**— Throughout the aforesaid sections of the Act, unless otherwise directed, for the words “State Government”, the word “Administrator” shall be substituted and there shall also be made in any sentence in which the words “State Government” occur, such consequential amendments as rules of grammar may require.

2. In section 1,-

(a) in sub-section (1), for the words and figures “The Bombay Police Act, 1951”, the words and figures “The Bombay Police Act, 1951 as extended to the Union territory of Daman & Diu” shall be substituted.

(b) in sub-section (2), for the words “State of Maharashtra”, the words “Union territory of Daman & Diu” shall be substituted;

(c) for sub-section(3), the following sub-section shall be substituted, namely :-

“(3) It shall come into force on such date as the Administrator may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be constituted as a reference to the commencement of that provision.”

3. In section 2,-

(a) for clause(1), the following clause shall be substituted namely:-

“(1) “Administrator” means the Administrator of the Union territory of Daman and Diu appointed by the President under article 239 of the Constitution ;”

(b) clauses (2), (3), (4) and (5) shall be omitted;

(c) for clause (6), the following clause shall be substituted, namely :-

“(6) “Inspector” means the Inspector of Police appointed for the Union territory of Daman & Diu ;”;

(d) clauses (7) and (7A) shall be omitted;

(e) clauses (9) and (10) shall be omitted;

(f) for clause (11), the following clause shall be substituted, namely :-

“(11) “Police Officer” means any member of the Police Force appointed or deemed to be appointed for the Union territory of Daman & Diu;”;

(g) clauses (12), (13), (13A), (14), (15), (16) and (17) shall be omitted.

4. In section 55,-

(a) for the words and figure “Whenever it shall appear in Greater Bombay and in other areas in which a Commissioner is appointed under section 7 to the Commissioner and in a district to the District Magistrate, the Sub-Divisional Magistrate or the District Superintendence specially empowered by the State Government in that behalf”, the words “Whenever it shall appear to the District Magistrate” shall be substituted;

(b) for the words “within the local limits of his jurisdiction or such area and any district or districts, or any part thereof, contiguous thereto within such time as such officer shall prescribe, and not to enter the area or the area and such contiguous districts, or part thereof, as the case may be or”, the words “within the local limits of his jurisdiction by such route and such time as such officer shall prescribe, and not to enter the area, or” shall be substituted.

5. In section 56,-

(a) for the words and figure “Whenever it shall appear in Greater Bombay and other areas for which a Commissioner has been appointed under section 7 to the Commissioner and in other area or areas to which the State Govt. may, by notification in the Official Gazette extend the provisions of this section, to the District Magistrate, or the Sub-Divisional Magistrate specially empowered by the State Government in that behalf”, the words “Whenever it shall appear to the District Magistrate”, shall be substituted;

(b) for the words “within the local limits of his jurisdiction or such area and any district or districts, or any part thereof, contiguous thereto by such route and within such time as the said officer may prescribe and not to enter or return to the said area or the area and such contiguous districts or part thereof, as the case may be, from which”, the words “within the local limits of his jurisdiction by such route and within such time as the said officer may prescribe and not to enter or return to the said area from which” shall be substituted.

6. In section 57,-

(a) for clauses (a), (b) and (c), the following clauses shall be substituted, namely :-

“(a) of an offence under Chapter XII, XVI or XVII of the India Penal Code, or

(b) twice, of an offence under the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 (104 of 1956), or

(c) thrice within a period of three years of an offence under the Abkari Act of 1956 of the Daman and Diu Liberated Areas or any other corresponding law for the time being in force in the Union territory of Daman and Diu.”

(b) for the words "the Commissioner, the District Magistrate or the Sub-Divisional Magistrate specially empowered by the State Government in this behalf", the words "the District Magistrate" shall be substituted ;

(c) for the words "within the local limits of his jurisdiction or such area and any district or districts, or any part thereof, contiguous thereto, by such route and within such time as the said officer may prescribe and not to enter or return to the area or the area and such contiguous districts, or part thereof, as the case may be, from which", the words "within the local limits of his jurisdiction or such area and any district or districts, or any part thereof, contiguous thereto by such route and within such time as the said officer may prescribe and not to enter or return to the area from which" shall be substituted.

7. For section 58, the following section shall be substituted, namely:—

"58. Period of operation of orders under sections 55, 56 and 57.— A direction made under section 55, 56 or 57 not to enter any particular area shall be for such period as may be specified therein and shall in no case exceed a period of two years from the date on which the person removes himself or is removed from the area, district or districts or part aforesaid."

8. For section 59, the following section shall be substituted, namely:—

"59. Hearing to be given before order under section 55, 56 or 57 is passed.— (1) Before an order under section 55, 56 or 57 is passed against any person the officer acting under any of the said sections or any officer above the rank of an Inspector authorised by that officer shall inform the person in writing of the general nature of the material allegations against him and give him a reasonable opportunity of tendering an explanation regarding them. If such person makes an application for the examination of any witness produced by him, the authority or officer concerned shall grant such application; and examine such witness, unless for reasons to be recorded in writing, the authority or officer is of opinion that such application is made for the purpose of vexation or delay. Any written statement put in by such person shall be filed with the record of the case. Such person shall be entitled to appear before the officer proceeding under this section by an advocate or attorney for the purpose of tendering his explanation and examining the witness produced by him.

(2) The authority or officer proceeding under sub-section (1) may, for the purpose of securing the attendance of any person against whom any order is proposed to be made under section 55, 56 or 57 require such person to appear before him and to pass a security bond with or without sureties for such attendance during the inquiry. If the person fails to pass the security bond as required or fails to appear before the officer or authority during the inquiry, it shall be lawful to the officer or authority to proceed with the inquiry and thereupon such order as was proposed to be passed against him may be passed."

9. In section 60, in sub-section (1), for the words and figures "section 55, 56, 57 or 57A", the words and figures "section 55, 56 or 57" shall be substituted.

10. In section 61, for the words and figures "section 55, 56, 57 or 57A", the words and figures "section 55, 56 or 57" shall be substituted.

11. In section 62,—

- (i) in sub-section (1), for the words and figures “section 55, 56, 57 or 57A”, the words and figures “section 55, 56 or 57” shall be substituted;
- (ii) In sub-section (2),—
 - (a) for the words “enter or return to the area, including any contiguous districts or part thereof, from which”, the words “enter or return to the area from which” shall be substituted; and
 - (b) for the words “or the area and any contiguous districts or part thereof” wherever they occur shall be omitted.

12. In section 63,—

- (a) for the words and figures “section 55, 56, 57 or 57A”, the words and figures “section 55, 56 or 57” shall be substituted; and
- (b) the words “or such area and any contiguous districts or part thereof, as the case may be” wherever they occur shall be omitted.

13. In section 63AA,—

- (a) for subsection (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(1) The Administrator or any other officer specially empowered by the Administrator in that behalf, may, in like circumstances and in like manner, exercise the powers exercisable by the District Magistrate under section 55, 56 or 57.”; and

- (b) in sub-section (2), for the words and figures “section 55, 56, 57 or 57A” the words and figures “section 55, 56 or 57” shall be substituted.

14. In section 71,—

- (a) the words “regulation and” shall be omitted; and
- (b) the figures “43” shall be omitted.

15. For section 72, the following section shall be substituted, namely:—

“72. When Police Officer may arrest without warrant.— Any officer may, without an order from a Magistrate and without a warrant, arrest any person who contravenes any order made under section 56, 57 or 63AA.”.

16. For section 141, the following section shall be substituted, namely:—

“141. Penalty for contravention of directions under section 55, 56, 57 or 63AA.— Whoever opposes or disobeys or fails to conform to any direction issued under section 55, 56, 57 or 63AA or abets opposition to or disobedience of any such direction shall, on conviction, be punished with imprisonment which may extend to one year but shall not, except for reasons to be recorded in writing, be less than four months, and shall also be liable to fine.”.

17. In section 142,—

- (a) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—
 “(a) in contravention of a direction issued to him under section 55, 56, 57 or 63-AA enters or returns without permission to the area from which he was directed to remove himself;”;
- (b) in clause (b), the words “or district aforesaid or part thereof” shall be omitted.

18. For section 157, the following section shall be substituted, namely :-

“157. Presumption in prosecutions for contravention of directions issued under section 55, 56, 57 or 63AA.- Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, in a prosecution for an offence for the contravention of a direction issued under section 55, 56, 57 or 63AA on the production of an authentic copy of the order, it shall, until the contrary is proved and the burden of proving which shall lie on the accused, be presumed-

- (a) that the order was made by the authority competent under this Act to make it ;
- (b) that the authority making the order was satisfied that the grounds on or the purpose for which it was made existed, and that it was necessary to make the same; and
- (c) that the order was otherwise valid and in conformity with the provisions of this Act.”.

19. In section 157A for the words “a Commissioner” and the word “Commissioner” wherever they occur, the word “Administrator” shall be substituted.

20. In section 159, for the words “No Revenue Commissioner, Magistrate or Police Officer shall be”, the words “The Administrator, any Magistrate or any Police Officer shall not be” shall be substituted.

21. In section 161, in sub-section (1), for the words “Revenue Commissioner, the Commissioner” and words “Revenue Commissioner, Commissioner”, the words “Administrator” shall be substituted.

[F. No. U-11015/1/2011-UTL]

K. K. PATHAK, Jt. Secy.

ANNEXURE

THE BOMBAY POLICE ACT, 1951 AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF DAMAN AND DIU

CHAPTER I

Preliminary

1. Short title, extent and commencement. (1) This Act may be called the Bombay Police Act, 1951.

(2) It extends to the whole of the State of Maharashtra.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, specify in this behalf and in that part of the State to which it is extended by the Bombay Police (Extension and Amendment) Act, 1959 (Bombay XXXIV of 1959), it shall come into force on such other date as that Government may, by like notification specify

2. Definitions. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context—

(1) "cattle" includes elephants, camels, horses, asses, mules, sheep, goats and swine;

(2) to (5) **Omitted.**

(5-A) "eating-house" means any place to which the public are admitted, and where any kind of food or drink is supplied for consumption on the premises by any person owning or having an interest in or managing such place, and includes a refreshment-room, boarding-house, coffee-house or a shop where any kind of food or drink is supplied to the public for consumption in or near such shop but does not include "a place of public entertainment."

(6) "Inspector-General", "Special Inspector-General", "Additional Inspector-General", "Commissioner", "Deputy Inspector-General", "Deputy Commissioner", "Assistant Commissioner", "District Superintendent", "Additional Superintendent", "Assistant Superintendent" and "Deputy Superintendent" means respectively the Inspector-General of Police, Special Inspector-General of Police, an Additional Inspector-General of Police, a Commissioner of Police including an Additional Commissioner of Police, a Deputy Inspector-General of Police, (including the Director of Police Wireless and Deputy Inspector-General of Police appointed under Sec. 8-A) a Deputy Commissioner of Police an Assistant Commissioner of Police, a District Superintendent of Police (including a Superintendent of Police appointed under Sec. 8-A or 22-A), an Additional Superintendent of Police, an Assistant Superintendent of Police and a Deputy Superintendent of Police appointed or deemed to be appointed under this Act;

(7) **Omitted.**

(7A) **Omitted.**

(8) "place" includes a building, a tent, a booth or other erection, whether permanent or temporary, or any area whether enclosed or open;

(9) to (10) **Omitted.**

(11) "Police officer" means any member of the Police Force appointed or deemed to be appointed under this Act, and includes a special or an additional Police officer appointed under Sec. 21 or 22;

(12) to (17) **Omitted.**

3. to 54. **Omitted.**

55. *Dispersal of gangs and body of persons.*

Whenever it shall appear in Greater Bombay and in areas in which a Commissioner is appointed under Sec. 7 to the Commissioner and in a district to the District Magistrate the Sub-Divisional Magistrate or the District Superintendent specially empowered by the State Government in that behalf, that the movement or encampment of any gang or body of persons in the area in his charge is causing or is calculated to cause danger or alarm or reasonable suspicion that unlawful designs are entertained by such gang or body or by members thereof, such officer may, by notification addressed to the persons appearing to be the leaders or chief men of such gang or body and published by beat of drum or otherwise as such officer thinks fit, direct the members of such gang or body so to conduct themselves as shall seem necessary in order to prevent violence and alarm, or disperse and each of them to remove himself outside the area within the local limits of his jurisdiction or such area and any district, or districts or any part thereof, contiguous thereto which in such time as such officer shall prescribe, and not to enter the area 4[or the area and such contiguous districts, or part thereof, as the case may be, or return to the place from which each of them was directed to remove himself.

56. *Removal of persons about to commit offence.*

Whenever it shall appear in Greater Bombay and other areas for which a Commissioner has been appointed under Sec. 7 to the Commissioner and in other area or areas to which State Government may, by notification in the Official Gazette, extend the provisions of this section, to the District Magistrate, or the sub. Divisional Magistrate specially empowered by the State Government in that behalf-

(a) that the movements or acts of any person are causing or calculated to cause alarm, danger or harm to person or property, or

(b) that there are reasonable grounds for believing that such person is engaged or is about to be engaged in the commission of an offence involving force or violence or an offence punishable under Chapters XII, XVI, or XVII of the Indian Penal Code (XLV of 1860), or in the abetment of any such offence, and when in the opinion of such officer witnesses are not willing to come forward to give evidence in public against such person by reason of apprehension on their part as regards the safety of their person or property,

(bb) that there are reasonable grounds for believing that such person is acting or is about to act (1) in any manner prejudicial to the maintenance of public order as defined in the Maharashtra Prevention of Communal, Antisocial and other Dangerous Activities Act, 1980, or (2) in any manner prejudicial to the maintenance of supplies of commodities essential of the community as

defined in the Explanation to sub-section (1) of Sec. 3 of the Prevention of Black-marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 (VII of 1980), or

(c) that an outbreak of epidemic disease is likely to result from the continued residence of an immigrant, the said officer may, by an order in writing duly served on him or by beat of drum or other wise as he thinks fit, direct such person or immigrant so to conduct himself as shall seem necessary in order to prevent violence and alarm [or such prejudicial act] or the outbreak or spread of such disease or to remove himself outside the area within the local limits of his jurisdiction or such area and any district or districts, or any part thereof, contiguous thereto by such route and within such time as the said officer may prescribe and not to enter or return to the said area or the area and such contiguous districts, or part thereof as the case may be from which he was directed to remove himself.

57. Removal of persons convicted of certain offences.

If a person has been convicted –

- (a) (i) of an offence under Chapters XII, XVI or XVII of the Indian Penal Code (XLV of 1860),
or
 - (ii) of any offence under Secs. 65, 66-A or 68 of the Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom. XLV of 1949), or
 - (iii) of an offence under Secs. 3, 4, 5, 6 or 9 of the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 (CIV of 1956), or
 - (iv) of an offence under Sec. 135 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), or
 - (v) of an offence under Sec. 4; or for accepting bets in any public street or thoroughfare or in any place to which the public have or permitted to have access or in any race course under Cl. (a) of Sec. 12, or under Sec 12-A of the Bombay Prevention of Gambling Act, 1867 (Bom. IV of 1867), or
- (b) twice or more of an offence under the Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom XXV of 1949) not being an offence under Secs. 66, 66-A or 68, or
- (c) twice or more of an offence under Sec- 122 or 124 of this Act, the Commissioner, the District Magistrate, or the Sub Divisional Magistrate specially empowered by the State Government in this behalf, if he has reason to believe that such person is likely again to engage himself in the commission of an offence similar to that for which he was convicted, may direct such person to remove himself outside the area within the local limits of his jurisdiction or such area and any district or districts, or any part thereof, contiguous thereto by such route and within such time as the said officer may prescribe and not to enter or return to the area or the areas and such contiguous district or districts or part thereof, as the case may be, from which he was directed to remove himself.

Explanation. For the Purpose of this section "an offence similar to that for which a person was convicted", shall mean-

- (i) in the case of a person, convicted of an offence mentioned in Cl. (a) (i) an offence falling under any of the chapters of the Indian Penal Code (XLV of 1860), and
- (ii) in case of a person convicted of an offence mentioned in Cl. (a) excluding sub-clause (i) thereof (b) and (c) an offence falling under the provisions of the Acts mentioned respectively in the said clauses. From the date on which the person removes himself or is removed from the area, district or districts or part aforesaid.

57-A. Omitted.

58. Period of operation of orders under Secs. 55, 56, 57 and 57-A.

A direction made under Secs. 55, 56 or 57 not to enter any particular area or such area and any district or districts, or any part thereof contiguous thereto, as the case may be, shall be for such period as may be specified therein and shall in no case exceed a period of two years, from the date on which the person removes himself or is removed from the area, district or districts or part aforesaid.

59. Hearing to be given before order under Secs. 55, 56, 57 and 57-A is passed.

(1) Before an order under Ss. 55, 56, 57 and 57-A is passed against any person the officer acting under any of the said sections or any officer above the rank of an Inspector authorized by that officer shall inform the person in writing of the general nature of the material allegations against him and give him a reasonable opportunity of tendering and explanation regarding them. If such person makes so application for the examination of any witness produced by him, the authority or officer concerned shall grant such application; and examine such witness, unless for reasons to be recorded in writing, the authority or officer is of opinion that such application is made for the purpose of vexation or delay. Any written statement put in by such person shall be filed with the record of the case. Such person shall be entitled to appear before the officer proceeding under this section by an advocate or attorney for the purpose of tendering his explanation and examining the witnesses produced by him.

(2) The authority or officer proceeding under sub-section (1) may, for the purpose of securing the attendance of any person against whom any order is proposed to be made under Secs. 55, 56, 57 and 57-A require such person to appear before him and to pass a security bond with or without sureties for such attendance during the inquiry. If the person fails to pass the security bond as required or fails to appear before the officer or authority during the inquiry, it shall be lawful to

the officer or authority to proceed with the inquiry and thereupon such order as was proposed to be passed against him, may be passed.

60. Appeal. (1) Any person aggrieved by an order made under Secs. 55, 56, 57 and 57-A may appeal to the State Government within thirty days from the date of such order.

(2) An appeal under this section shall be preferred in duplicate in the form of a memorandum, setting forth concisely the grounds of objection to the order appealed against, and shall be accompanied by that order or a certified copy thereof.

(3) On receipt of such appeal, the State Government may, after giving a reasonable opportunity to the appellant to be heard either personally or by a pleader advocate or attorney and after such further inquiry, if any, as it may deem necessary, confirm, vary or cancel or set aside the order appealed against, and make its order accordingly:

Provided that the order appealed against shall remain in force pending the disposal of the appeal, unless the State Government otherwise directs.

(4) In calculating the period of thirty days provided for an appeal under this section, the time taken for granting a certified copy of the order appealed against, shall be excluded.

61. Finality of order passed by State Government in certain case.

Any order passed under Secs. 55, 56, 57 and 57-A or by the State Government under Sec. 60 shall not be called in question in any Court except on the ground that the authority making the order or any officer authorised by it had not followed the procedure laid down in sub-section (1) of Sec. 59 or that there was no material before the authority concerned upon which it could have based its order on the ground that the said authority was not of opinion that witnesses were unwilling to come forward to give evidence in public against the person in respect of whom an order was made under Sec. 56.

62. Procedure on failure of person to leave the area and his entry therein after removal.

(1) If a person to whom a direction has been issued under Secs. 55, 56, 57 and 57-A to remove himself from an area

(i) fails to remove himself as directed, or

(ii) having so removed himself, except with the permission in writing of the authority making the order as provided in sub-section (2), enters the area within the period specified in the order, the authority concerned may cause him to be arrested and removed in police custody to such place outside the area as the said authority may in each case prescribe.

(2). The authority making an order under Secs. 55, 56, 57 and 57-A may in writing permit any person in respect of whom such order has been made to enter or return to the area, including any contiguous districts or part thereof, from which he was directed to remove himself, for such

temporary period and subject to web conditions as may be specified in such permission and may require him to enter into a bond with or without surety for the due observance of the conditions imposed. The authority aforesaid may at any time revoke any such permission. Any person who with such permission enters or returns to such area shall observe the conditions imposed, and at the expiry of the temporary period for which he was permitted to enter or return, or on the earlier revocation of such permission, shall remove himself outside such area, or the area and any contiguous districts or part thereof, and shall not enter therein or return thereto within the unexpired residue of the period specified in the original order made under Secs. 55, 56, 57 and 57-A without a fresh permission. If such person fails to observe any of the conditions imposed, or to remove himself accordingly, or having so removed himself enters or returns to the area, or the area and any contiguous districts or part thereof, without fresh permission, the authority concerned may cause him to be arrested and removed in police custody to such place outside the area as that authority may in each case prescribe.

63. *Temporary permission to enter or return to the area from which a person was directed to remove himself.*

(1) The State Government or any officer specially empowered by the State Government in that behalf may, by order, permit any person in respect of whom an order has been made under Secs. 55, 56, 57 and 57-A to enter or return for a temporary period to the area, or such area and any contiguous districts or part thereof, as the case may be, from which he was directed to remove himself, subject to such conditions as it 8[or he] may by general or special order specify, and which such person accepts and may, at any time, revoke any such permission.

(2) In permitting a person under sub-section (1) to enter or return to 3[the area or such area and any contiguous districts, or part thereof, as the case may be, from which he was directed to remove himself, the State Government or such officer may require him to enter into bond with or without surety for the observance of the conditions imposed.

(3) Any person permitted under sub-section (1) to enter or return to the area or such area and any contiguous districts, or part thereof, as the case may be, from which he was directed to remove himself shall surrender himself at the time and place and to the authority specified in the order or in the order revoking the said order, as the case may be.

63-AA. *Powers of externment of State Government and officers specially empowered.*

(1) The State Government or any officer specially empowered by the State Government in that behalf, may, in like circumstances and in like manner, exercise the powers exercisable, in any area for which a Commissioner is appointed by the Commissioner, and in a district by the District Magistrate, Sub-Divisional Magistrate or Superintendent specially empowered by the State Government in that behalf, as the case may be, under Secs. 55, 56, 57 and 57-A with this modification that it shall be lawful for the State Government or the officer specially empowered to direct the members of such gang or body, or persons or immigrants, or persons convicted or person declared to be beggars, as the case may be, to remove themselves from, and not to enter

or return to, any local area, or any such area and any district or part thereof, whether contiguous thereto or not.

(2) The provisions of Secs. 58, 59, 60, 61, 62 and 63 shall *mutatis mutandis* apply to the exercise of any powers under this section, as they apply to the exercise any powers under Secs. 55, 56, 57 and 57-A.

64. to 70. **Omitted.**

71. *Duty of Police to see orders issued under Secs. 43, 55, 56, 57, 57-A or 63-AA are carried out.*

It shall be the duty of the Police to see that every regulation and direction made by any authority under Secs. 43, 55, 56, 57, 57-A or 63-AA, is duly obeyed, to warn persons who from ignorance fail to obey the same and to arrest any person who willfully disobeys the same.

72. *When Police officer may arrest without warrant.*

Any police officer may, without any order from a Magistrate and without a warrant, arrest-

(1) any person who has been concerned in an offence punishable under Sec 121 or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists, of his having been concerned in such offence;

(2) any person who contravenes a rule or order under Cl. (x) of sub-section (1) of Sec. 33 or an order or notification under Secs. 36, 37, 56, 57, 57-A or 63-AA ;

(2-A) any person who contravenes any order made under sub-section (1) of Sec. 63-A ;

(3) any person who commits an offence punishable under Sec. 122 or Sec. 136.

73. to 140. **Omitted.**

141. *Penalty for contravention of directions under Secs. 55, 56, 57, 57-A or 63-AA.*

Whoever opposes or disobeys or fails to conform to any direction issued under Secs. 55, 56 3[57, 57-A or 63-AA or abets opposition to or disobedience of any such direction shall, on conviction, be punished with imprisonment which may extend to one year but shall not, except for reasons to be recorded in writing, be less than four months, and shall also be liable to fine.

142. *Penalty for entering without permission area from which a person is directed to remove himself or overstaying when permitted to, return temporarily.*

Without prejudice to the power to arrest and remove a person in the circumstances and in the manner provided in Sec. 62, any person who –

(a) in contravention of a direction issued to him under Secs. 55, 56, 57, 57-A or 63-AA enters or returns without permission to the area, or any district or districts or part thereof, from which he was directed to remove himself;

(b) enters or returns to any such area or district aforesaid or part thereof with permission granted under sub-section (2) of Sec. 62, but fails, contrary to the provisions thereof, to remove himself outside such area at the expiry of the temporary period for which he was permitted to enter or return or on the earlier revocation of such permission, or having removed himself at the expiry of such temporary period or on revocation of the permission, enters or returns thereafter without fresh permission, shall on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to two years, but shall not, except for reasons to be recorded in writing, be less than six months; and shall also be liable to fine.

143. *Penalty for failure in surrender in accordance with sub-section (3) of Sec. 3.*

Whoever fails without sufficient cause to surrender in accordance with sub-section (3) of Sec. 63 shall, on conviction, be punished with imprisonment which may extend to two years and shall also be liable to fine.

144. to 154. **Omitted.**

155. *Method of proving orders and notifications.*

Any order or notification published or issued by the State Government or by a Magistrate or officer under any provision of this Act, and the due publication or issue thereof may be proved by the production of a copy thereof in the Official Gazette, or of a copy thereof signed by such Magistrate, or officer, and by him certified to be a true copy of an original published or issued according to the provisions of the section of the Act applicable thereto.

156. *Rules and orders not invalidated by defect of form or irregularity in procedure.*

No rule, order, direction, adjudication, inquiry or notification made or published, and no act done under any provision of this Act, or of any rule made under this Act, or in substantial conformity to the same, shall be deemed illegal, void, invalid or insufficient by reason of any defect of form or any irregularity of procedure.

157. *Presumption in prosecutions for contravention of directions issued under Sec. 55, 56, 57, 57-A or 63-AA.*

Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, in a prosecution for an offence for the contravention of a direction issued under Sec. 45, 56, 57 or 63- AA on the production of an authentic copy of the order, it shall, until the contrary is proved and the burden of proving which shall lie on the accused, be presumed-

- (a) that the order was made by the authority competent under this Act to make it ;
- (b) that the authority making the order was satisfied that the grounds on or the purpose for which it was made existed, and that it was necessary to make the same; and
- (c) that the order was otherwise valid and in conformity with the provisions of this Act.

157-A. *Officers holding charge of or succeeding to vacancies competent to exercise powers.*

Whenever in consequence of the office of a Commissioner, Magistrate or Police officer becoming vacant, any officer holds charge of the post of such Commissioner, Magistrate, or Police officer or succeeds, either temporarily or permanently, to his office, such officer shall be competent to exercise all the powers and perform all the duties respectively conferred and imposed by this Act on such Commissioner, Magistrate or Police officer, as the case may be.

158. *Forfeiture of bond entered into by person permitted to enter or return to the area from which he was directed to remove himself.*

If any person permitted under sub-section (1) of Sec.63 fails to observe any condition imposed under the said sub-section or in the bond entered into by him under sub-section (2) of the said section his bond shall be forfeited and any person bound thereby shall pay the penalty thereof or show cause to the satisfaction of the court why such penalty should not be paid.

159. *No Magistrate or Police officer to be liable to penalty or damage for act done in good faith in pursuance of duty.*

No Revenue Commissioner, Magistrate] or Police officer shall be liable to any penalty or to payment of damages on account of an act done in good faith, in pursuance or intended pursuance or any duty imposed or any authority conferred on him by any provision of this Act or any other law for the time being in force or any rule, order or direction made or given therein.

160. *No public servant liable as aforesaid for giving effect in good faith to any rule, order or direction issued with apparent authority.*

No public servant or person duly appointed or authorized shall be liable to any penalty or to payment of any damages for giving effect in good faith to any such order or direction issued with apparent authority by the State Government or by a person empowered in that behalf under this Act or any rule, order or direction made or given there under.

161. *Suits or prosecutions in respect of acts done under colour of duty as aforesaid not to be entertained or to be dismissed if not instituted within prescribed period.*

(1) In any case of alleged offence by the Revenue Commissioner, a Magistrate, Police officer or other person, or of a wrong alleged to have been done by such Revenue Commissioner, Magistrate, Police officer or other person, by any act done under colour or in excess of any such duty or authority as aforesaid, or wherein, it shall appear to the court that the offence or wrong if committed or done was of the character aforesaid, the prosecution suit shall not be entertained, or shall be dismissed, if instituted, more than six months after the date of the act complained of:

Provided that, any such prosecution against Police officer may be entertained by the court, if instituted with the previous sanction of the State Government within two years from the date of the offence.

(2) In suits as aforesaid one month's notice of suit to be given with sufficient description of wrong complained of. In this case of an intended suit on account of such a wrong as aforesaid, the person intending to sue shall be bound to give to the alleged wrong doer one month's notice at least of the intended suit with sufficient description of the wrong complained of, failing which such suit shall be dismissed.

(3) Plaint to set forth service of notice and tender of amend. The plaint shall set forth that a notice as aforesaid has been served on the defendant and the date of such service, and shall state whether any, and if any, what tender of amends has been made by the defendant. A copy of the said notice shall be annexed to the plaint endorsed or accompanied with a declaration by the plaintiff of the time and manner of service thereof.

162. Omitted.

163. *Public notices how to be given.*

Any public notice required to be given under any of the provisions of this Act shall be in writing under the signature of a competent authority and shall be published in the locality to be affected thereby, by affixing copies thereof in conspicuous public places, or by proclaiming the same with beat of drums, or by advertising the same in such local newspapers- English or regional language or Hindi- as the said authority may deem fit, or by any two or more of these means and by any other means it may think suitable.

164. to 167. Omitted.

Schedule-I Omitted.

Schedule-II Omitted.